5 जनसेवा की भावना के बल पर ऊँचाइयों तक

6 मुख्यमंत्री क्वीस ऑन द व्हील्स को करेंगे फ्लैग ऑफ

6 करोड़ों की भूमि पर कर रहे अवैध निर्माण

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 44 प्रति सोमवार, 09 मार्च 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मप्र विधानसभा में गूंजा आरकेडीएफ प्रकरण: जवाबदेही से बचती रही मोहन सरकार

मेडिकल कॉलेज आवंटन पर घिरी सरकार, सुनील कपूर और चिकित्सा मंत्री पर उठे गंभीर सवाल

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उस मुद्दे से गूंज उठी, जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस को जन्म दे दिया है। मामला है आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी और आरकेडीएफ कॉलेज समूह के मालिक सुनील कपूर से जुड़ा, जिस पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। विशेष रूप से राज्य के चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल की चुप्पी और कथित भूमिका ने विवाद को और गहरा कर दिया है। मध्यप्रदेश विधानसभा में उठा यह मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं है, बल्कि शासन की

विश्वसनीयता की कसौटी है। सुनील कपूर को मेडिकल कॉलेजों का आवंटन, निविदा प्रक्रिया में कथित बदलाव, मंत्री की चुप्पी और बंद कमरे की बैठकों की चर्चा ये सभी तथ्य मिलकर एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। जनता यह जानना चाहती है कि क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निर्णय पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर लिए जा रहे हैं या फिर राजनीतिक संरक्षण और निजी हित हावी हैं। चिकित्सा मंत्री और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इन सवालों का स्पष्ट, दस्तावेजी और तथ्यों पर आधारित उत्तर दें। लोकतंत्र में सत्ता अस्थायी होती है, लेकिन निर्णयों का प्रभाव स्थायी। इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकरण में सत्य सामने आए ताकि न केवल दोषियों को दंड मिले, बल्कि भविष्य में ऐसी आशंकाओं की गुंजाइश भी समाप्त हो। (शेष पेज 2 पर)

जनता के विश्वास के प्रतीक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नेतृत्व और छत्तीसगढ़ के विकास की नई दिशा

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासी संस्कृति से समृद्ध धरती ने समय-समय पर ऐसे नेतृत्व को जन्म दिया है जिसने प्रदेश को नई दिशा दी है। इन्हीं नेताओं में प्रमुख नाम है विष्णुदेव साय का, जो आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक संवेदनशील, कर्मठ और जनप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हैं। एक सामान्य आदिवासी परिवार से निकलकर प्रदेश के सर्वोच्च पद तक पहुँचना उनकी संघर्षशीलता और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रमाण है। विष्णुदेव साय का व्यक्तित्व केवल राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जनभावनाओं को समझने वाले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जनता के बीच बिताया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने सत्ता और जनता के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया। अपने दो वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और जनोन्मुख बनाने की दिशा में अनेक पहलें की हैं।

(शेष पेज 2 पर)

ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही दुनिया में मची उथल-पुथल

-विजया पाठक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले एक साल में पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। जब से वह राष्ट्रपति बने हैं तबसे पूरे विश्व में उथल-पुथल मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के 2025 में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही 'अमेरिका फर्स्ट' नीति ने वैश्विक व्यवस्था में भारी उथल-पुथल मचा दी है। हाल ही में ईरान पर हुए हमले ने तो ट्रंप की दादागिरी उजागर हो गई है। ट्रंप अपनी दादागिरी पूरे विश्व में थोपना चाहते हैं। खासकर छोटे देशों पर तो अनुचित कार्यवाही से नहीं चूक रहे हैं। अपने हितों को साधने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था। ईरान के खिलाफ चल रहा मौजूदा अभियान ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे आक्रामक और जोखिम भरी कार्रवाई मानी जा रही है। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। इसका खुला उद्देश्य ईरान की सरकार को गिराना है। यह फैसला उन्होंने बिना कांग्रेस की मंजूरी और बिना लंबी सार्वजनिक बहस के लिया। इससे पहले 2003 में इराक युद्ध के बाद पहली बार मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा अमेरिकी सैन्य जमावड़ा हुआ।9/11 के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। बाद में बराक ओबामा ने ड्रोन हमले किए। लेकिन ये अभियान पहले से मंजूर या चल रहे युद्ध क्षेत्रों तक सीमित थे। (शेष पेज 3 पर)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हुआ प्रदेश से नक्सलियों का खात्मा

नक्सल प्रभावित अन्य राज्यों से बेहतर रहा मप्र का रिकॉर्ड

-विजया पाठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया है, विशेष रूप से बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों में बड़ी सफलता हासिल की है। 10 हार्डकोर नक्सलियों के समर्पण और लगातार अभियानों (2025-26) के माध्यम से पुलिस ने लाल आतंक की कमर तोड़ी है, जिसे विकास के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट में 2 प्रमुख नक्सलियों (दीपक और रोहित) के समर्पण के बाद राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया। दीपक और रोहित पर क्रम से 29 लाख रुपए और 14 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, और दोनों ने मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जाहिर करते हुए सरेंडर किया। दिसंबर 2025 में, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 10 हार्डकोर, वर्दीधारी और सशस्त्र नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।

(शेष पेज 5 पर)

मेडिकल कॉलेज आवंटन पर घिरी सरकार, सुनील कपूर और चिकित्सा मंत्री पर उठे गंभीर सवाल

(पेज 1 का शेष)

सदन में उठा गंभीर सवाल

विधानसभा में विपक्ष के विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनील कपूर पर राजस्थान में फर्जी डिग्री बांटने का आपराधिक मामला दर्ज है और उन्हें हाल ही में गिरफ्तार भी किया गया था। मरकाम ने सदन को अवगत कराया कि 22 जनवरी को हुई गिरफ्तारी के कारण 23 जनवरी को प्रस्तावित कटनी मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन कार्यक्रम को अचानक निरस्त करना पड़ा। यदि यह तथ्य सही हैं, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्ति को, जिस पर गंभीर आपराधिक आरोप लंबित हों, राज्य में महत्वपूर्ण चिकित्सा परियोजनाएं कैसे सौंपी जा सकती हैं? विपक्ष का तर्क है कि यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राजनीतिक संरक्षण का मामला प्रतीत होता है।

पीपीपी मॉडल या विशेष लाभ

सरकार ने सुनील कपूर को धार, बैतूल, कटनी और पन्ना जिलों में पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का जिम्मा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि निविदा की शर्तों में बदलाव कर ऐसे प्रावधान जोड़े गए, जिनसे कपूर को सीधा लाभ मिला। यदि किसी एक समूह को बार-बार बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजिमी है। क्या निविदा प्रक्रिया वास्तव में निष्पक्ष थी? क्या अन्य इच्छुक संस्थाओं को समान अवसर मिला? क्या तकनीकी और वित्तीय मानकों में ढील दी गई? ये वे प्रश्न हैं जिनका स्पष्ट उत्तर जनता जानना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने निविदा की शर्तें इस प्रकार तैयार कीं कि प्रतियोगिता सीमित हो जाए और चयन पूर्व-निर्धारित दिखे। यदि ऐसा हुआ है, तो यह न केवल प्रशासनिक चूक है बल्कि नीति निर्माण में पक्षपात का संकेत भी देता है।

चिकित्सा मंत्री की चुप्पी पर सवाल

सदन में जब यह मामला उठा, तब चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कोई स्पष्ट और विस्तृत जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी ने संदेह को और बढ़ा दिया। सूत्रों के अनुसार, एक बंद कमरे में सुनील कपूर के करीबियों और मंत्री के समर्थकों के बीच बैठक हुई थी। यद्यपि इस बैठक के आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज है। यदि मंत्री पूरी तरह निर्दोष हैं और प्रक्रिया पारदर्शी रही है, तो उन्हें खुलकर सामने आकर सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिए। लोकतंत्र में जवाबदेही से बचना स्वयं संदेह को जन्म देता है। मंत्री की भूमिका केवल नीतिगत स्वीकृति तक सीमित थी या उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप किया यह स्पष्ट होना आवश्यक है।

आर्थिक हित नीति निर्धारण पर हावी हो रहे हैं

यह पूरा विवाद केवल एक व्यक्ति या एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक प्रश्न को सामने लाता है कि क्या सरकारें निजी निवेश के नाम पर विवादित व्यक्तियों को संरक्षण दे रही हैं? क्या राजनीतिक समीकरण और आर्थिक हित नीति निर्धारण पर हावी हो रहे हैं? यदि सुनील कपूर पर दर्ज मामलों की जांच लंबित है, तो कम से कम तब तक उन्हें बड़े सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स देने से परहेज किया जाना चाहिए था। सार्वजनिक धन और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या पक्षपात दूरगामी नुकसान पहुंचा सकता है।

निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवाती मोहन सरकार?

इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण है निष्पक्ष और पारदर्शी जांच। यदि आरोप निराधार हैं, तो सरकार को आधिकारिक दस्तावेजों, निविदा प्रक्रिया के विवरण और मूल्यांकन मानकों को सार्वजनिक करना चाहिए। इससे न केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब मिलेगा, बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। यदि कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों।

कटनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग

कटनी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की मांग थी कि वहां पूर्णतः सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए। उनका तर्क था कि सरकारी कॉलेज में फीस नियंत्रण में रहती है और सामाजिक उत्तरदायित्व अधिक होता है। लेकिन सरकार ने पीपीपी मॉडल को प्राथमिकता दी। सत्ता पक्ष का कहना है कि केवल "सरकारी" होने से ही गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होती। यदि निजी भागीदारी से बेहतर संसाधन और प्रबंधन मिल सकता है, तो उसे नकारना व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, जब निजी भागीदार पर ही गंभीर आरोप हों, तब यह तर्क कमजोर पड़ जाता है।

जनता के विश्वास के प्रतीक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का विकास

(पेज 1 का शेष)

किसान हित में ऐतिहासिक निर्णय

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार खेती और किसान हैं। एक किसान परिवार से आने वाले विष्णुदेव साय किसानों की समस्याओं और आवश्यकताओं को भली-भांति समझते हैं। इसी संवेदनशीलता का परिणाम है कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली से पहले एकमुश्त भुगतान की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की राशि होली से पहले किसानों को प्रदान की जाएगी। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि किसानों के आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला निर्णय है। पिछले दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है। इस वर्ष के भुगतान के साथ यह राशि बढ़कर लगभग 35 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी, बाजारों में खरीद-फरोख्त बढ़ेगी और कृषि से जुड़े उद्योगों में भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा।

कृषि क्षेत्र में नई सोच

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सबसे अधिक मानी जाती है। इस नीति से किसानों को उचित मूल्य मिलने के साथ-साथ खेती के प्रति उनका उत्साह भी बढ़ा है। राज्य सरकार का यह प्रयास दर्शाता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कृषि को केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि ग्रामीण समृद्धि का आधार मानते हैं।

औद्योगिक विकास की नई संभावनाएँ

विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि औद्योगिक विकास की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप अब तक 7 लाख 83 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना ही नहीं है, बल्कि रोजगार के नए अवसर सृजित करना और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करना भी है। इससे युवाओं को रोजगार मिलने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल

विष्णुदेव साय के सुशासन में महिला सशक्तिकरण को विशेष महत्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह निर्णय महिलाओं के सम्मान और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में लगभग 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और वे परिवार के निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा 42 हजार 878 महिला स्व-सहायता समूहों को आसान ऋण के रूप में 129.46 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 4.81 लाख महिलाओं को 237 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। राज्य की 19 लाख से अधिक महिलाओं को पूरक पोषण आहार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 की स्थापना की गई है। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर 52.20 करोड़ रुपये की लागत से 179 महतारी सदनों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर मिल सकें। महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए नवा रायपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण भी प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएँ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह योजना उन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है जो खेती पर निर्भर होने के बावजूद भूमि के स्वामी नहीं हैं। आवास के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। राज्य में अब तक लगभग 26 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किए गए हैं। इससे हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ है।

आधारभूत सुविधाओं का विस्तार

राज्य सरकार स्वच्छ पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के 41 लाख से अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाया जा चुका है। जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से 3208 गाँवों को लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही राज्य के सभी गाँवों में विद्युत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज हो रही है।

अधोसंरचना और कनेक्टिविटी में प्रगति

डबल इंजन सरकार के तहत छत्तीसगढ़ में परिवहन और अधोसंरचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना के माध्यम से बस्तर क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जगदलपुर-विशाखापट्टनम और रायपुर-विशाखापट्टनम सड़क परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिल रही है। प्रदेश के 32 नगरीय निकायों में नॉलेज-बेस्ड सोसाइटी के निर्माण के लिए लाइट हाउस परियोजना की पहल भी की जा रही है, जिससे शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

जननेता के रूप में पहचान

विष्णुदेव साय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जनता से सीधे संवाद करने में विश्वास रखते हैं। वे प्रदेश के हर वर्ग- किसान, मजदूर, महिला, युवा और आदिवासी समुदाय की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करते हैं। उनके नेतृत्व में कई योजनाएँ शुरू की गई हैं, जैसे नियद नेल्ला नार, अखरा निर्माण योजना और अन्य सामाजिक विकास कार्यक्रम। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करना है। विष्णुदेव साय का अब तक का कार्यकाल यह दर्शाता है कि यदि नेतृत्व ईमानदार, संवेदनशील और दूरदर्शी हो तो विकास की राह स्वयं प्रशस्त हो जाती है। उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की जो नीति अपनाई है, वह छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और सशक्त राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। उनकी कार्यशैली में सरलता, पारदर्शिता और जनसेवा का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि आज वे केवल एक मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि जनता के विश्वास के प्रतीक बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के विकास की यह यात्रा उनके नेतृत्व में आने वाले वर्षों में और भी नई ऊँचाइयों को छूने की क्षमता रखती है।

बजट 2026-27 में दिखी आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की झलक

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। राज्य के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है। इस बार के बजट में आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की साफ झलक दिख रही है। बजट में ऐसे प्रावधान किये गये हैं जो राज्य को आय के अन्य स्त्रोतों को संबल प्रदान करेंगे। बजट की विशेषता यह है कि खर्च के साथ-साथ आय पर पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह दूसरा बजट है। जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। खासकर कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। वहीं महिलाओं के लिए भी कई प्रकल्प प्रारंभ किये हैं। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 दीर्घकालिक लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए 2030 के मध्यकालिक लक्ष्य को भी निर्धारित किया है, एक स्पष्ट रोड-मैप के साथ इस ओर आगे बढ़ रहा है।

इस बार बजट की थीम SANKALP है, जो कि जनता-जनार्दन के प्रति प्रतिबद्धता को, निष्ठा को, समर्पण और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। सरकार ने बजट में अधोसंरचना को विशेष स्थान दिया है। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए आज लगभग 47 हजार करोड़ के कार्य हो रहे हैं, जो 2013-14 की तुलना में लगभग 24 गुना अधिक है। छत्तीसगढ़ में अनेक बड़े-बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रायपुर-रांची-धनबाद एक्सप्रेस-वे, रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे, खरसिया से परमालकसा रेलवे लाईन, केंदरी में नया कोचिंग टर्मिनल, रायपुर से सारंगढ़-बिलाईगढ़ तक फोरलेन, कोरबा-अंबिकापुर नई रेल लाइन, डोंगरगढ़-कटघोरा रेल लाईन ले रहे हैं। इस वर्ष लोक निर्माण विभाग अंतर्गत लगभग 9,450 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

साय सरकार समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक एवं सर्वग्राही होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लक्ष्य न केवल तेजी से विकास करना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि विकास की इस दौड़ में समाज का कोई भी वर्ग या प्रदेश का कोई भी अंचल पीछे न रह जाए। छत्तीसगढ़ ने अपनी विकास यात्रा में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किये हैं। 05 हजार करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह सफर, आज 35 गुना बढ़कर 01 लाख 72 हजार करोड़ का आकार ले रहा है और इस सफर में राज्य के हर व्यक्ति, गरीब, युवा, किसान, महिला, उद्यमी सबका योगदान रहा है। समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू तुलनात्मक रूप से पीछे रह गये क्षेत्रों का विकास भी है। सदैव यह प्रयास किया है कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र भी, विकास-पथ पर मैदानी क्षेत्रों से कंधे से कंधा मिलाकर चलें। बस्तर में नक्सलवाद से मुक्ति किसी की भी कल्पनाओं से परे थी, लेकिन मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया और इसे कर के दिखा रहे हैं। बस्तर शांति, पुनर्निर्माण और भरोसे की ओर लौट रहा है। रोड नेटवर्क को बढ़ाने के साथ-साथ सिंचाई, नहर, बांध जैसी संरचनाएँ जो आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।

बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर

छत्तीसगढ़ के समावेशी एवं सर्वांगीण विकास तथा खुशहाली का रास्ता खेतों से, खलिहानों से, मेड़ों से, नहरों से और तालाबों से होकर किसानों के घर तक पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में कृषि एक व्यवसाय नहीं बल्कि संस्कृति है, पहचान है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव है। 2025-26 में 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पिछले तीन खरीफ सीजन में 437 लाख मीट्रिक टन धान की ऐतिहासिक खरीदी की है। जिससे किसानों के खाते में लगभग 01 लाख 40 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान संभव हो रहा है। सरकार ने 'कृषक उन्नति योजना' के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता और कृषि विकास को गति मिलेगी। कृषि पंपों के लिए 5,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, वहीं भूमिहीन कृषि परिवारों के समर्थन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग, एग्रो-फॉरेस्ट प्रोसेसिंग, राइस मिल और पोल्ट्री फार्म जैसे रोजगारमूलक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में मदद मिलेगी। मतनार और देउरगाँव बैराज (2,024 करोड़) जैसी सिंचाई परियोजनाओं को सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने के लिये डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो पहले अछूते थे। भूमिहीन कृषि परिवारों को सहायता प्रदान कर उनकी आजीविका सुरक्षा को बढ़ाया गया है।

नारी शक्ति का उत्थान

छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति को महतारी वंदन योजना से जोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक पहचान दिलाने की बात कही थी। योजना अंतर्गत 70 लाख माताओं-बहनों को अभी तक 24 किश्तों में, 14 हजार करोड़ से अधिक की राशि सरकार ने जारी की है। बजट में इसके लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता का जो मंच दिया है, उसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है तथा लगभग 05 लाख बहनें आर्थिक तरक्की कर लखपति दीदी बन चुकीं हैं। प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन हेतु 800 करोड़, पूरक पोषण आहार योजना हेतु 650 करोड़, पोषण अभियान एवं कुपोषण मुक्ति योजनाओं हेतु 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 120 करोड़ तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

निवेश का फोकस

छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग 60 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आता है, इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का लगभग 48 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का लगभग 35 प्रतिशत योगदान है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 रोजगार पर केन्द्रित है तथा विगत वर्ष लगभग 1 हजार उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से न केवल शासकीय अस्पताल बल्कि गैर शासकीय अस्पतालों में भी 05 लाख रूपये तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 25 विकासखण्डों में डायलिसिस केन्द्र तथा 50 विकासखण्डों में जनऔषधि केन्द्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 183 करोड़,राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

UPSC में मध्यप्रदेश के प्रतिभावानों ने टॉप-10 में बनाई जगह

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा-2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इस वर्ष परीक्षा में मध्यप्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इस बार प्रदेश के दो प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों ने टॉप-10 में जगह बनाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। भोपाल के ईशान भटनागर ने ऑल इंडिया रैंक 5 प्राप्त की। धार जिले के प्राक्षल सेकेट्री ने 8वीं रैंक हासिल की। इसके अलावा अशोकनगर के चितवन जैन ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 17वीं रैंक प्राप्त की है। शुक्रवार को जारी हुए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा 2025 के नतीजो में मध्य प्रदेश के 16 युवाओं ने कामयाबी का परचम फहराया है। इंदौर के अक्षत बल्दवा और अनन्या शर्मा, भोपाल के ईशान और खंडवा की रूपल ने सफलता पाई है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों ने अगस्त 2025 में लिखित परीक्षा और फरवरी 2026 में पर्सनैलिटी टेस्ट में हिस्सा लिया था।

ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही दुनिया में मची उथल-पुथल

(पेज 1 का शेष)

इसके उलट ट्रंप ने नए मोर्चे खोले। उन्होंने क्रिसमस के दिन नाइजीरिया में हमला कराया, कैरिबियाई इलाके में ड्रग तस्करी करने वाली नावों को डुबोया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कराकस से पकड़ लिया। ट्रंप की रणनीति साफ है। जमीनी सैनिक नहीं भेजना, लंबे समय तक किसी देश में फंसे नहीं रहना, और बहुत कम समय में भारी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना। इसे वे अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए जरूरी बताते हैं। सनकी ट्रंप ने सभी के लिए हालात बेकाबू कर दिये हैं। अपनी रणनीतियों को थोपकर वह जताना चाहता है कि अमेरिका ही सबसे ताकतवर है।

ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही ग्रीनलैंड को अपने देश में मिलाने की इच्छा व्यक्त की थी। अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अभियान चलाया है। उन्होंने कनाडा, मैक्सिको, पनामा नहर और गाजा पट्टी को भी अपने देश में मिलाने या उन पर नियंत्रण करने का सुझाव दिया है। 12 महीने में 7 देशों पर किया हमला, अब 8वीं की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप ने एक साल में सात देशों पर सैन्य कार्रवाई कर रिकॉर्ड बनाया, 2025 में एयर स्ट्राइक के मामले में वे बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल से भी आगे रहे। खुद को युद्ध विरोधी बताने वाले ट्रंप ने ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साल में सात देशों पर सैन्य कार्रवाई कर रिकॉर्ड बनाया, 2025 में एयर स्ट्राइक के मामले में वे बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल से भी आगे रहे। आधुनिक अमेरिकी इतिहास में शायद ही किसी राष्ट्रपति ने उतने देशों पर सैन्य हमले कराए हों, जितने डोनाल्ड ट्रंप ने किए। उन्होंने सात अलग-अलग देशों पर कार्रवाई की। इनमें से तीन देश ईरान, नाइजीरिया और वेनेजुएला ऐसे थे, जहां इससे पहले अमेरिका ने कभी सैन्य हमला नहीं किया था. साल 2025 में ट्रंप ने जितने हवाई हमलों को मंजूरी दी, उतने चार साल में राष्ट्रपति बाइडेन ने भी नहीं दिए थे। 28 फ़रवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू की, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि वह ऐसे परमाणु हथियार बना रहा है जो अमेरिकी सहयोगियों के लिए ख़तरा हैं और 'जल्द ही अमेरिका तक पहुंच सकते हैं

यह मामला इसलिए खास है क्योंकि ट्रंप ने खुद को चुनाव के दौरान युद्ध विरोधी नेता के तौर पर पेश किया था। उनका कहना था कि वे अमेरिका को नए युद्धों में नहीं उलझाएंगे। अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर मतभेद हैं। ईरान पर हमले को गलत और घिनौना बताया है। दिलचस्प बात यह है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 2023 में एक आर्टिकल में कहा था कि ट्रंप की सबसे बड़ी विदेश नीति उपलब्धि यह थी कि उन्होंने कोई नया युद्ध शुरू नहीं किया। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि बातचीत की कोशिशें असफल रहीं, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए शुरू किया गया यह युद्ध अमेरिकी जानों की कीमत के लायक है। यह बहस ट्रंप के पूरे कार्यकाल में जारी रहने की संभावना है।

आज पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। पूरे विश्व में व्यापारिक, आर्थिक उथल पुथल मची हुई है। जो देश युद्ध भी नहीं लड़ रहे वह भी इसकी चपेट में आ गये हैं। सबसे बड़ी चिंता तो यह भी है कि किसी को पता नहीं है कि यह युद्ध और कब तक चलेगा।

आर्थिक और व्यापार युद्धः ट्रंप के प्रशासन ने सहयोगियों और विरोधियों दोनों पर सीमा शुल्क लगा दिया है, जिससे वैश्विक शेयर बाजारों में खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने नाटो और अन्य सुरक्षा गठबंधनों के प्रति प्रतिबद्धता को कम किया है, जिससे यूरोप की सुरक्षा संरचना कमजोर हो रही है।

युद्ध का भारत पर प्रभाव

ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध भारत के लिए मुसीबत लेकर आया है। यही कारण है कि आज तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बयान नहीं आया है। संबंधों की बात करें तो इजराइल और ईरान से भारत के संबंध बेहतर हैं। अमेरिका से भले ही कुछ तनातनी चल रही है। लेकिन यहां एक बात जरूर गौर करने वाली है कि ईरान हमेशा से भारत का अच्छा मित्र रहा है। हर मुसीबत में ईरान का साथ दिया है। आज जब ईरान मुसीबत में है तो भारत न्यूट्रल की स्थिति में है। वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की हत्या कर दी गई है। ईरान युद्ध में जल रहा है। भारत कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहां विपक्ष इस मामले पर मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जहां तक व्यापारिक हितों की बात करें तो अभी भले ही असर नहीं हो रहा है लेकिन युद्ध और आगे चलने से भारत की मुश्किलें और अधिक बढ़ने वाली हैं। विपक्ष का तो यहां तक कहना है कि मोदी अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गये हैं। भारत के लिए यह एक जटिल स्थिति है जहाँ एक ओर रक्षा और तकनीक में बेहतर रिश्तों की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर व्यापार समझौते में चुनौतियाँ और अमेरिकी दबाव का जोखिम बना हुआ है। ट्रंप के आने से पारंपरिक वैश्विक व्यवस्था चरमरा रही है। यह दौर "अपेक्षा से कहीं अधिक उथल-पुथल" का है, जहाँ पुरानी सुरक्षा गारंटी कमजोर हो रही है और देशों को अपने बलबूते पर नई रणनीतियां बनानी पड़ रही हैं। आज भारत ऐसी स्थिति में खड़ा हो गया है कि वह न तो युद्ध के पक्ष में दिखाई दे रहा है और न ही विरोध में।

मोदी की चुप्पी के क्या मायने?: राहुल गांधी पहले भी विदेश नीति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घेरते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की चुप्पी से भारत की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस कमजोर हो रही है। कांग्रेस ने भी इस पर सपोर्ट किया और कहा कि सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए।

सम्पादकीय

किस मोड़ पर आकर रूकेगा अमेरिका, इज़राइल और ईरान का युद्ध?

पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम एशिया की राजनीति अत्यंत जटिल और संवेदनशील हो गई है। विशेष रूप से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए यह प्रश्न बार-बार उठता है कि क्या ईरान वास्तव में अमेरिका और इजराइल का अकेले सामना कर रहा है या फिर यह संघर्ष कई परोक्ष शक्तियों और रणनीतिक हितों का परिणाम है। दरअसल, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति तक जाती हैं, जब ईरान में शाह की सत्ता समाप्त हुई और इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जबकि ईरान ने भी अमेरिकी नीतियों का तीखा विरोध किया। इसी बीच इजराइल भी ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा मानता रहा है, विशेषकर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से विवाद चलता रहा है। इस संदर्भ में 2015 में ईरान परमाणु समझौता (JCPOA) हुआ था, जिसमें ईरान और कई विश्व शक्तियों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और बदले में उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाना था। लेकिन 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया।

इजराइल का मानना है कि यदि ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाता है तो इससे पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यही कारण है कि इजराइल कई बार ईरान के सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। दूसरी ओर, ईरान भी यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए है, न कि हथियार बनाने के लिए। हालांकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि ईरान पूरी तरह अकेला है। वास्तव में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश पूर्णतः अकेला नहीं होता। ईरान के कुछ रणनीतिक साझेदार भी हैं, जिनमें रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं। ये देश कई वैश्विक मंचों पर ईरान के साथ कूटनीतिक सहयोग करते हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया में भी ईरान के कुछ प्रभावशाली सहयोगी संगठन हैं, जैसे हिज़्बुल्लाह और हमास, जो क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी यह सच है कि सैन्य और आर्थिक दृष्टि से अमेरिका और इजराइल की संयुक्त शक्ति के सामने ईरान की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देती है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति है, जबकि इजराइल तकनीकी रूप से अत्यंत उन्नत सैन्य क्षमता रखता है। इन दोनों देशों के पास आधुनिक हथियार प्रणाली, उन्नत खुफिया नेटवर्क और मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी है।

दूसरी ओर, ईरान ने भी अपनी रक्षा रणनीति को अलग तरीके से विकसित किया है। उसने मिसाइल तकनीक, ड्रोन क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत किया है। इसके अलावा ईरान "प्रत्यक्ष युद्ध" की बजाय "अप्रत्यक्ष रणनीति" का उपयोग करता है, जिसमें वह क्षेत्रीय सहयोगियों और प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से अपना प्रभाव बनाए रखता है। यही कारण है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में ईरान का प्रभाव लगातार बना हुआ है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह संघर्ष केवल तीन देशों के बीच का सीधा टकराव नहीं है, बल्कि यह व्यापक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। इसमें ऊर्जा संसाधनों, क्षेत्रीय प्रभुत्व, सुरक्षा चिंताओं और वैचारिक मतभेदों जैसे कई कारक शामिल हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ गंभीर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना जरूर कर रहा है, लेकिन वह पूरी तरह अकेला नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसके कुछ सहयोगी और क्षेत्रीय प्रभाव मौजूद हैं, जो इस शक्ति संतुलन को जटिल बनाते हैं। इसलिए पश्चिम एशिया में स्थायी शांति तभी संभव है जब सभी पक्ष संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दें, क्योंकि किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष का प्रभाव केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है।

सियासी गहमागहमी

मध्यप्रदेश प्रेम को नहीं छोड़ पा रहे शिवराज

मध्यप्रदेश की राजनीति इन दिनों बड़े रोचक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। वजह हैं देश के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी प्रदेश में बढ़ती सक्रियता ने भाजपा के कई नेताओं की धड़कनें कुछ तेज कर दी हैं। दिल्ली में मंत्री बनने के बाद आमतौर पर नेता अपने-अपने मंत्रालय में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन शिवराज का दिल अभी भी मध्यप्रदेश की मिट्टी में ही धड़कता दिखता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता शायद यही सोच रहे होंगे कि "मामा" आखिर इतने फुर्सत में कैसे हैं कि दिल्ली और भोपाल दोनों जगह बराबर नजर आ रहे हैं। कभी किसी जिले में कार्यक्रम, कभी किसी कार्यकर्ता के घर चाय, तो कभी किसानों से सीधा संवाद-मानो केंद्रीय मंत्री नहीं, फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव अभियान चल रहा हो। राजनीति के जानकार इसे अनुभव और सक्रियता बताते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कुछ लोग इसे "अत्यधिक उत्साह" भी कह रहे हैं। दरअसल समस्या यह नहीं कि शिवराज जी सक्रिय हैं, समस्या यह है कि वे बहुत ज्यादा सक्रिय हैं।

आखिर क्यों लगाई राहुल गांधी ने पटवारी को फटकार?

मध्यप्रदेश की राजनीति में हाल ही में उस समय हलचल मच गई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंदौर दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की अव्यवस्थित गतिविधियों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को फटकार का सामना करना पड़ा। यह घटना केवल एक क्षणिक नाराजगी नहीं थी, बल्कि संगठनात्मक, अनुशासन और नेतृत्व की अपेक्षाओं को लेकर एक स्पष्ट संदेश भी थी। दरअसल, जब किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का दौरा होता है तो स्थानीय संगठन से यह उम्मीद की जाती है कि कार्यक्रम सुव्यवस्थित और अनुशासित तरीके से संपन्न हो। लेकिन इंदौर में कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा की गई धक्का-मुक्की और अव्यवस्था ने कार्यक्रम की गरिमा को प्रभावित किया। इसी कारण राहुल गांधी ने असंतोष जताते हुए संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी। राजनीतिक दृष्टि से यह घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक संकेत भी है कि केवल राजनीतिक मुद्दों पर आक्रामकता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि संगठनात्मक अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं और उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वे कार्यकर्ताओं को संगठित और नियंत्रित रखने में प्रभावी भूमिका निभाएँ।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

रंगों और मोहब्बत के पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

होली के रंग आप सभी के जीवन को नई आशाओं, नए उमंग और अनगिनत खुशियों से भर दे।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के नाम पर भाजपा सिर्फ पाखंड करती है। भाजपा की सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय में 2007 में लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की थी।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

जनसेवा की भावना के बल पर ऊँचाइयों तक पहुँचे नित्यानंद राय

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपने संघर्ष, संगठन क्षमता और जनसेवा के माध्यम से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। उन्हीं नेताओं में एक प्रमुख नाम है नित्यानंद राय का। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव काफी मजबूत रहा है और वे लंबे समय से संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। नित्यानंद राय का जन्म 1 जनवरी 1966 को बिहार के हाजीपुर के एक सामान्य परिवार में हुआ। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता, जहाँ उन्होंने समाज की समस्याओं और आम जनता की कठिनाइयों को करीब से देखा। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने क्षेत्र में ही प्राप्त की। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की और युवावस्था से ही सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे। विद्यार्थीकाल में ही उनमें नेतृत्व क्षमता और संगठन कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। राजनीति में उनका प्रवेश मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर उन्होंने संगठन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। धीरे-धीरे अपनी मेहनत, निष्ठा और कार्यकुशलता के कारण वे पार्टी के विश्वसनीय नेताओं में गिने जाने लगे। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

नित्यानंद राय का राजनीतिक सफर तब और मजबूत हुआ जब वे बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने हाजीपुर क्षेत्र से विधायक के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व किया और क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रयास किए। उनकी लोकप्रियता और संगठन क्षमता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपीं। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष 2019 में हुए 2019 भारतीय आम चुनाव में नित्यानंद राय ने बिहार के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया। इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। वे भारत सरकार में भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में कार्य करने लगे। गृह मंत्रालय में उनकी भूमिका कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा तथा विभिन्न प्रशासनिक मामलों से संबंधित रही है। एक राजनेता के रूप में नित्यानंद राय की पहचान सादगी, संगठनात्मक दक्षता और कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण के लिए की जाती है। वे अक्सर जनता से सीधे संवाद करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए जाने जाते हैं। बिहार में भाजपा को मजबूत बनाने में उनका योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। वे युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए प्रेरित भी करते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी नित्यानंद राय सक्रिय रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में कई पहलें की हैं। इसके अलावा वे विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों की सहायता करने का प्रयास करते रहे हैं। इस प्रकार नित्यानंद राय का जीवन संघर्ष, परिश्रम और जनसेवा की भावना से प्रेरित रहा है। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। आज वे न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा यह दर्शाती है कि समर्पण, मेहनत और जनसेवा की भावना के बल पर व्यक्ति समाज और देश की सेवा करते हुए ऊँचाइयों तक पहुँच सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हुआ प्रदेश से नक्सलियों का खात्मा

(पेज 1 का शेष)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश ने लगभग 35 साल नक्सलवाद का दंश झेला। यह एक बड़ी चुनौती थी, पर राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और नक्सल विरोधी अभियान में शामिल जवानों की प्रतिबद्धता से 11 दिसंबर 2025 को नक्सलवाद प्रदेश के नक्शे से पूरी तरह मिटा दिया गया। मध्यप्रदेश की धरती से नक्सलवाद को समूल खत्म करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नक्सलवाद और लाल आतंक देश के हर हिस्से में विकास आधारित गतिविधियों में बाधक था। अब इससे प्रभावित क्षेत्रों में विकास को एक नई दिशा और एक नई रफ्तार मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में वर्ष 1988-90 से नक्सली गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। नक्सलियों ने आम नागरिकों को डरा-धमकाकर परेशान किया और सरकार के विकास कार्यों में भी रुकावटें डालीं। नक्सली पुलिस की बसों को भी आग के हवाले कर देते थे। नक्सलियों ने विपक्षी दल की सरकार में मंत्री रहे लिखीराम कावरे की बालाघाट जिले में उनके घर से निकालकर सरेआम हत्या कर दी थी। प्रदेश में 35 सालों के लंबे समय तक नक्सलियों से संघर्ष जारी रहा, जिसमें कई आम नागरिक और पुलिस व सुरक्षाबलों के जवानों को अपने प्राण गंवाने पड़े।

नक्सलवाद उन्मूलन अभियान के कुछ प्रमुख तथ्य

- मध्यप्रदेश में वर्ष 1988 से 1990 के बीच नक्सल गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। प्रदेश में मंडला, डिंडौरी और बालाघाट नक्सल प्रभावित जिले रहे।
- नक्सलियों को हथियार डालकर जीवन से जुड़ने का अवसर देने के लिए राज्य सरकार ने 'पुनर्वास से पुनर्जीवन' अभियान प्रारंभ किया।
- सरकार की इसी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर दिसंबर 2025 में करीब 2.36 करोड़ रुपए की इनामी राशि वाले 10 नक्सलियों ने पुलिस लाईन, बालाघाट में सरेंडर कर दिया।
- 11 दिसंबर 2025 को मध्यप्रदेश ने 35 वर्षों से चले आ रहे लाल आतंक को समाप्त कर नक्सल मुक्त बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।
- वर्ष 2025 में नक्सल विरोधी अभियानों में 16 मुठभेड़ों/एक्सचेंज ऑफ फायर में 13 हार्डकोर नक्सली मारे गए और एक की गिरफ्तारी हुई।

देश के अंदर अकेले 2025 में ही 312 वामपंथी उग्रवादी कार्यकर्ताओं को मार गिराया गया है, जिनमें प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के महासचिव और आठ अन्य पोलित ब्यूरो/केंद्रीय समिति सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा, 836 वामपंथी उग्रवादी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और 1,639 ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय समिति के सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव (उर्फ भूपति) ने गढ़चिरोली के भामरागड में महाराष्ट्र पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 70 वर्षीय भूपति, जिन पर 6 करोड़ रुपये का इनाम है, को उग्रवादी आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक माना जाता है।

झारखंड में नक्सलवाद

झारखंड में नक्सलवाद एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा और विकासात्मक चुनौती है, जो मुख्य रूप से गरीबी, आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी उपेक्षा, विस्थापन और सामाजिक-आर्थिक असमानता के कारण उपजी है। माओवादी हिंसक गतिविधियों द्वारा विकास कार्यों को बाधित करते हैं, लेकिन अब पुलिस और सुरक्षाबलों की सख्त कार्रवाई से इसका प्रभाव 22 जिलों से घटकर 2025 तक 09 प्रमुख जिलों (जैसे पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार) तक सीमित हो गया है। उनके साथ आत्मसमर्पण करने वाले अन्य विद्रोहियों में दो राज्य क्षेत्रीय समिति के सदस्य, 10 मंडल समिति के सदस्य और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता शामिल थे।

प्रशासन, पुलिस और समाज का समन्वय

मध्यप्रदेश मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता रही समन्वय। मुख्यमंत्री स्तर से लेकर जिला प्रशासन, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय समाज- सभी को एक साझा लक्ष्य के तहत जोड़ा गया। योजनाबद्ध ढंग से क्षेत्रवार रणनीति बनाई गई, स्थानीय परिस्थितियों को समझा गया और हर कार्रवाई से पहले उसके दूरगामी परिणामों पर विचार किया गया। यही कारण है कि अभियान केवल सुरक्षा कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विकास योजनाओं, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के विस्तार से भी जुड़ा रहा। इससे नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों का भरोसा सरकार पर और मजबूत हुआ।

छत्तीसगढ़ में कार्रवाई पर उठते सवाल

इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर कई प्रश्न खड़े हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के भीतर ही गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर असहमति की आवाजें सुनाई दीं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि गृहमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री की पूर्ण जानकारी और व्यापक रणनीतिक योजना के बिना कुछ निर्णय लिए, जिनका परिणाम तात्कालिक रूप से हिंसक टकराव के रूप में सामने आया। विशेष रूप से हिडमा जैसे कुख्यात नक्सली नेता के संदर्भ में यह चर्चा तेज हुई कि यदि समग्र योजना और संवाद की संभावनाओं पर काम किया जाता, तो स्थिति अलग हो सकती थी। आलोचकों का कहना है कि बिना पर्याप्त तैयारी और दीर्घकालिक रणनीति के की गई कार्रवाइयाँ न केवल मानव जीवन के लिए जोखिमपूर्ण होती हैं, बल्कि सरकार की छवि और विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं।

राजनीतिक आरोप और प्रशासनिक छवि

छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि तात्कालिक निर्णयों ने राज्य सरकार को अनावश्यक विवादों में घेर दिया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे कदमों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की छवि को नुकसान पहुँचा और नक्सल विरोधी अभियान की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न लगे। यद्यपि सरकार की ओर से इन आरोपों का खंडन भी किया गया है, फिर भी यह बहस यह संकेत देती है कि आंतरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर समन्वय और नेतृत्व की एकरूपता कितनी आवश्यक है।

रणनीति बनाम तात्कालिकता

इन दोनों राज्यों के उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि नक्सलवाद जैसी समस्या का समाधान केवल हथियारों से नहीं हो सकता। जहाँ मध्यप्रदेश में योजनाबद्ध, चरणबद्ध और संवाद-आधारित नीति अपनाई गई, वहीं छत्तीसगढ़ में तात्कालिक कार्रवाई की छवि उभरी। एक ओर आत्मसमर्पण के रिकॉर्ड बने, दूसरी ओर मुठभेड़ों और विवादों की चर्चा हुई। यह अंतर केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि वैचारिक भी है कि राज्य नक्सलियों को केवल शत्रु के रूप में देखता है या भटके हुए नागरिक के रूप में, जिन्हें मुख्यधारा में लौटने का अवसर दिया जा सकता है।

नक्सल-मुक्ति की राह से मिली सीख और संदेश

नक्सल-मुक्त भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब सभी राज्य एक संतुलित नीति अपनाएँ- जहाँ सुरक्षा बलों की सशक्त भूमिका हो, वहीं संवाद, विकास और पुनर्वास की भी उतनी ही मजबूत व्यवस्था हो। मध्यप्रदेश का अनुभव यह बताता है कि राजनीतिक नेतृत्व की स्पष्ट सोच, प्रशासनिक अनुशासन और मानवीय दृष्टिकोण से बड़े बदलाव संभव हैं। वहीं छत्तीसगढ़ का प्रसंग यह चेतावनी देता है कि बिना समन्वय और योजना के उठाए गए कदम, भले ही उद्देश्य सही हों, लेकिन परिणाम जटिल हो सकते हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल एक राज्य या एक सरकार की नहीं, बल्कि राष्ट्र की साझा जिम्मेदारी है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालिया अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि नेतृत्व की भूमिका निर्णायक होती है। जहाँ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने संयम, रणनीति और संवाद से इतिहास रचा, वहीं छत्तीसगढ़ में उठे सवाल यह याद दिलाते हैं कि आंतरिक सुरक्षा जैसे विषय पर हर निर्णय सोच-समझकर, सामूहिक विमर्श और स्पष्ट योजना के साथ लिया जाना चाहिए। नक्सलमुक्त भारत की दिशा में यही संतुलित और दूरदर्शी मार्ग सबसे प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

सीएम धामी ने की हल्दवानी में कानून व्यवस्था व विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, अतः निर्माण कार्यों के दौरान जनता को अनावश्यक असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और जवाबदेही के साथ करें। कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग आपसी जिम्मेदारियों को एक-दूसरे पर न डालें और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हों। उन्होंने हल्द्वानी नगर के बच्चीनगर सहित अन्य क्षेत्रों में सिंचाई विभाग की नहरों के चौड़ीकरण एवं मरम्मत संबंधी प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

धामी ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने सभी संवेदनशील स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए जाने, सोलर फेंसिंग व तारबाड़ प्रणाली को मजबूत करने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को ठोस एवं कारगर उपाय अपनाने के लिए कहा, ताकि जनहानि और फसलों को होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। वनाग्नि की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने फायर लाइन (अग्निरोधक खाइयों) को दुरुस्त रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने, रेंजवार मॉनिटरिंग करने और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वनाग्नि की किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री क्वींस ऑन द व्हील्स को करेंगे फ्लैग ऑफ, देश भर की 25 महिला बाइकर्स करेंगी भोपाल से खजुराहो की 1,400 किमी लंबी बाइक ट्रेल

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से सुबह 9 बजे 'क्वींस ऑन द व्हील्स' के तीसरे संस्करण को फ्लैग ऑफ किया। प्रदेश के समृद्ध व ऐतिहासिक पर्यटन गंतव्यों को देश-दुनिया में प्रचारित करने के उद्देश्य से 25 महिला सुपर बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 'क्वींस ऑन द व्हील्स' के पिछले दो संस्करणों की सफलता के बाद, महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता एवं विरासत का यह 7 दिवसीय आयोजन भोपाल से खजुराहो तक लगभग 1,400 किलोमीटर लंबी बाइक ट्रेल को पूरा करेगा। सचिव पर्यटन और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि एमपी टूरिज्म बोर्ड की पहल क्वींस ऑन द व्हील्स' केवल एक बाइक राइड नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, साहस और मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं पर्यटन धरोहर का उत्सव है। हमें गर्व है कि देशभर से आईं 25 महिला सुपरबाइकर्स इस अनूठी यात्रा के माध्यम से भोपाल से खजुराहो तक प्रदेश के विविध पर्यटन स्थलों का अनुभव करेंगी और उन्हें देश-दुनिया तक पहुंचाने में सहभागी बनेंगी। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का उद्देश्य ऐसे नवाचारपूर्ण आयोजनों के माध्यम से प्रदेश को एक सुरक्षित, रोमांचक और विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

13 मार्च को भोपाल में होगा समापन

भोपाल से शुरू होकर यह 7-दिन की यात्रा सांची, उदयगिरि, चंदेरी, शिवपुरी, कूनो, ग्वालियर, दतिया, ओरछा और खजुराहो से होते वापस भोपाल में 13 मार्च को समाप्त होगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के इस कदम से राज्य की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को प्रमुखता देगा, साथ ही मध्य प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित और समृद्धिशाली पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह अभियान कम-ज्ञात स्थलों का प्रचार करेगा, रूरल टूरिज्म सर्किट्स को मजबूत करने और राज्य भर में रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम बनेगा।

मंदिर की आड़ में रेलवे की करोड़ों की भूमि पर कर रहे अवैध निर्माण

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। देश में आस्था के नाम पर न जाने लोग अपने उल्लू कब तक सीधा करते रहेंगे। अपने आस्तिक मंसूबों को साकार करने के लिए धर्म कार्य की संज्ञा देकर अपने स्वार्थ सिद्धि या बैर निकालने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही मामला गाडरवारा रेलवे पुलिस कॉलोनी में अवस्थित मां काली मंदिर के समक्ष सामने आया है। जहां रेलवे के कुछ पूर्व कर्मचारी, कुछ अन्य दूरस्थ वार्ड के निवासी जो व्यवस्था निर्माण के नाम पर मंदिर हेतु लोगों से धन की उगाही करते रहते हैं। अब स्थानीय प्रशासन की नाक तले मंदिर के समक्ष पड़ी रेलवे की करोड़ों की उपयोगी भूमि पर बाउंड्रीवॉल का निर्माण कर अधिग्रहीत कर रहे हैं व अपने उपयोग के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस पर स्थानीय रेल प्रशासन भी चुप नजर आ रहा है। पूर्व में भी इसी स्थान के बड़े हिस्से को चारदीवारी कर कब्जाने का प्रयास किया था उपरोक्त समय स्थानीय प्रशासन के दवाब में उस अवैध निर्माण को ढहा दिया गया था, किंतु अब होली पर समानांतर छुट्टियों की आड़ में पुनः अवैध निर्माण का कार्य चालू कर दिया है। आसपास के निवासियों से बातचीत में जो यहां दशकों से निवासरत है। पाया गया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, पूर्व में ऐसे निर्माण पर कार्यवाही हुई थी किंतु वर्तमान में कोई कार्यवाही न होना स्थानीय प्रशासन व पूर्व कर्मचारी की मिलीभगत की आशंका को दर्शाता है।

भारतीय नौसेना अभ्यास में शामिल होकर लौट रहे ईरानी जहाज़ पर अमेरिकी हमला सरासर ग़लतः अजय खरे

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रीवा। समता सम्पर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लोकतंत्र सेनानी अजय खरे ने कहा कि मेजबान भारतीय नौसेना के मिलन बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास के विशाल आयोजन की मेहमान नवाजी में शामिल होकर विशाखापट्टनम से स्वदेश लौट रहे ईरानी समुद्री जहाज 'आईरिस देना' पर अमेरिकी नौसेना का बिना किसी चेतावनी के हिंद महासागर क्षेत्र में तारपीडो से निशाना साधकर डुबोया जाना अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग कानून का सरासर उल्लंघन है। इससे शांत हिंद महासागर क्षेत्र भी युद्ध लपेट में आ गया है। जहाज पर सवार लगभग 180 ईरानी नाविकों में से करीब 87 शवों को श्रीलंका की नौसेना ने बरामद किया वहीं 32 का श्रीलंका के गॉल में ईलाज चल रहा है। शेष को समुद्र क्षेत्र में खोजा जा रहा है। खरे ने कहा ईरानी जहाज आईरिस देना भारत के प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र में नहीं, बल्कि श्रीलंका के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में डुबाया गया है। यह जहाज श्रीलंका के गॉल से लगभग 20-40 समुद्री मील दक्षिण में डूबा, जो भारत की 22 किमी (12 समुद्री मील) की संप्रभु सीमा से बाहर है। अमेरिका ने ऐसा करके न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून एवं मानवता की धज्जियां उड़ाई बल्कि भारत को भी नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे समय श्रीलंका जैसे छोटे देश ने आगे आकर बचाव कार्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है। खरे ने कहा कि कहा कि ईरान के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया में अमेरिका के द्वारा ईरानी जहाज पर हुए हमले को भारत के मेहमान पर हुआ हमला बताया गया है। जिसे अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग कानून का सरासर उल्लंघन कहा है। जहाज को बिना किसी चेतावनी हमला कर डुबोया गया। जहाज में युद्ध की कोई सामग्री नहीं होने का दावा भी किया गया है। अंतरराष्ट्रीय कानून कहता है कि युद्ध जैसी स्थिति में भी हमलावर देश के द्वारा घायलों का इलाज कराया जाएगा लेकिन अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह तो जहाज डुबोकर, भाग खड़ा हुआ। अमेरिका का यह कायराना हमला हिंद महासागर क्षेत्र के चौकीदार भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है। मोदी सरकार को इस बात का तत्काल संज्ञान लिया जाना चाहिए। श्री खरे ने कहा कि अमेरिका के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र को युद्ध की लपेट में लेना भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बड़ी चुनौती है।

भविष्य की वास्तविकता है सस्टेनेबिलिटी

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

सस्टेनेबिलिटी यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि वे वापस प्रकृति में लौट सकें। या यूं समझें वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि भविष्य की पीढ़ियां भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। दुनिया तेजी से बदल रही है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और उपभोक्तावाद की इस दौड़ में मानवता ने कई महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की हैं, लेकिन इन उपलब्धियों की कीमत हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों ने चुकाई है। आज, जब हम अपने आसपास के वातावरण की ओर देखते हैं, तो हमें एक बात स्पष्ट होती है। अगर हमने अभी भी अपनी जीवनशैली और उपभोग के तरीकों में बदलाव नहीं किया, तो हमारा भविष्य अस्थिर होगा। सस्टेनेबल विकास (सतत विकास) का मतलब केवल पर्यावरण की सुरक्षा नहीं है; इसका संबंध एक ऐसे संतुलित विकास से है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच तालमेल बैठाकर सभी की भलाई सुनिश्चित करे। इसके लिए आर्थिक, पर्यावरणीय, और सामाजिक इन तीन क्षेत्रों में नीतियों को एक साथ काम करना होगा। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। तापमान में वृद्धि, समुद्र के जलस्तर का बढ़ना और चरम मौसम की घटनाएँ, जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात। इन सबका परिणाम न केवल पर्यावरणीय हानि में होता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता भी बढ़ती है। कृषि उत्पादकता घट रही है, जिससे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इन समस्याओं के बीच, अगर हमें भविष्य को सस्टेनेबल बनाना है, तो हमें सभी स्तरों पर समग्र और ठोस कदम उठाने होंगे।

सस्टेनेबिलिटी की शुरुआत हमें अपनी रोजमर्रा की जीवनशैली से करनी होगी। इसमें सबसे पहले हमें अपनी उपभोग की आदतों पर ध्यान देना होगा। प्लास्टिक जैसी वस्तुएं, जो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती हैं, उनका इस्तेमाल कम करना जरूरी है। इसके अलावा, 'मिनिमलिज्म' (कम से कम उपयोग करने की आदत) की ओर बढ़ना होगा, जिससे हम केवल वही खरीदें और उपयोग करें जो हमारे लिए वास्तव में आवश्यक हो। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलविद्युत जैसे विकल्पों का इस्तेमाल न केवल जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करेगा, बल्कि यह पर्यावरणीय प्रदूषण को भी कम करेगा। हमें अपने घरों में ऊर्जा-बचत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए और ऊर्जा की खपत को कम करने के तरीकों को अपनाना चाहिए, जैसे दिन के उजाले में काम करने की आदत डालना।

जल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन हमारी लापरवाही के कारण यह तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और मानवजनित गतिविधियों के चलते दुनिया के कई हिस्सों में जल संकट गहरा रहा है। ऐसे में जल की बचत और संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा, जलस्रोतों की सफाई और पुनर्स्थापना भी जरूरी है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल भंडार छोड़ सकें। कृषि में सस्टेनेबिलिटी लाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि परंपरागत कृषि प्रणाली ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर गहरा दबाव डाला है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जैविक खेती और परंपरागत कृषि प्रणालियों की ओर वापसी करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा, 'किसान-उपभोक्ता कड़ी' को भी सशक्त बनाना जरूरी है, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ता को जैविक और ताजा उत्पाद प्राप्त हो सके। सस्टेनेबिलिटी का संदेश समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हमें सस्टेनेबिलिटी से जुड़े मुद्दों पर स्कूलों, कॉलेजों और समाज में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने होंगे। बच्चों और युवाओं को पर्यावरणीय शिक्षा से जोड़ना होगा ताकि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सजग हो सकें। इसके साथ ही, हमें सस्टेनेबल तकनीकों और नवाचारों को भी बढ़ावा देना होगा, ताकि हम नई पीढ़ी को ऐसी तकनीकों से लैस कर सकें जो पर्यावरण के अनुकूल हों। सरकार की नीतियों का भी सस्टेनेबल विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे कानून और नीतियां बनाई जानी चाहिए जो प्राकृतिक संसाधनों के अनावश्यक दोहन को रोकें और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें। सरकार को ऊर्जा की खपत, जल संरक्षण, और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए कठोर मानदंड स्थापित करने चाहिए। साथ ही, उद्योगों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि वे अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में सस्टेनेबल तरीकों का पालन करें।

सस्टेनेबल विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में भी मदद करता है। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग गरीबी, भूख, और असमानता से जूझ रहे हैं। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी का लक्ष्य केवल पर्यावरण को बचाना नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को विकास की धारा से जोड़ना है। हमें महिलाओं, हाशिए पर रहने वाले लोगों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना होगा, ताकि वे अपनी जीवनशैली को सस्टेनेबल बना सकें और विकास की प्रक्रिया में बराबरी से भाग ले सकें। सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक वैश्विक चुनौती है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का विनाश और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं सभी देशों को प्रभावित करती हैं। ऐसे में हमें वैश्विक स्तर पर सहयोग और समझौते करने होंगे। पेरिस समझौते जैसी पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन यह जरूरी है कि सभी देश अपनी जिम्मेदारियों को समझें और मिलकर इन चुनौतियों का सामना करें।

सस्टेनेबल भविष्य के लिए केवल सरकार और संगठनों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। हम सभी को अपने स्तर पर छोटे-छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे ऊर्जा की बचत करना, जल का संरक्षण करना, और सस्टेनेबल उत्पादों का उपयोग करना। इसके अलावा, हम अपने आसपास के लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं, ताकि सामूहिक प्रयासों से हम एक सस्टेनेबल समाज का निर्माण कर सकें। सस्टेनेबल भविष्य की दिशा में हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह जरूर है कि अगर हम अभी भी चेत गए और ठोस कदम उठाए, तो हम एक सस्टेनेबल, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह भविष्य न केवल हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा, बल्कि हम सबके लिए एक बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार बनेगा। अब समय आ गया है कि हम सस्टेनेबिलिटी को अपनी जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाएं और इस ग्रह को एक बार फिर से संतुलित और समृद्ध बनाएं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष

आधी आबादी का पूर्ण आकाश

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2026 केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक बदलते युग की पहचान है। इस वर्ष महिला दिवस का यह अवसर और भी खास हो गया है क्योंकि इसके साथ ही रंग पंचमी का उत्सव भी जुड़ा है। जैसे रंग पंचमी जीवन के विविध रंगों और उल्लास का प्रतीक है, वैसे ही आज की नारी अपनी प्रतिभा के हर रंग आत्मविश्वास, मेधा, साहस और करुणा से दुनिया को परिचित करा रही है। आज की नारी का संकल्प है कि वह समाज, परिवार और अपने लक्ष्यों के बीच तालमेल बिठाते हुए जीवन के हर रंग को खुलकर जिए। भारत की संसद से लेकर गाँवों की चौपालों तक आज एक नई गूँज सुनाई दे रही है, यह गूँज है उस नारी शक्ति की, जो अब केवल विकास की लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुकी है। भारत आज 'महिला विकास' की पारंपरिक अवधारणा से आगे बढ़कर 'महिला-नीत विकास' की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अंतरिक्ष के रहस्यों से लेकर स्टार्टअप इकोसिस्टम तक, देश की बेटियाँ हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं।

वैश्विक संदर्भः समावेश में निवेश इस वर्ष की अंतरराष्ट्रीय थीम

हमें एक स्पष्ट संदेश देती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, समावेश का अर्थ केवल महिलाओं को संख्यात्मक रूप से शामिल करना नहीं है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर का स्थान देना है। आज जब विश्व सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब महिलाओं की भागीदारी केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आर्थिक और नीतिगत मजबूती की शर्त बन चुकी है। भारत भी इस वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वह नीति निर्माण हो, डिजिटल अर्थव्यवस्था हो या जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रयास—भारतीय महिलाओं का नेतृत्व आज दुनिया के सामने एक प्रेरक उदाहरण है।

इतिहास के झरोखे सेः 'रोटी और सम्मान' की पहली पुकार

आज की इन उपलब्धियों को देखते हुए उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद करना भी आवश्यक है जहाँ से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास 1908 के न्यूयॉर्क की उन सड़कों से जुड़ा है, जहाँ श्रमिक महिलाओं ने पहली बार "ब्रेड एंड रोजेस"अर्थात रोटी और सम्मान—की मांग की थी। वर्ष 1910 में क्लारा जेटकिन के प्रस्ताव के बाद इसे वैश्विक स्वरूप मिला और 1911 में पहली बार इसे औपचारिक रूप से मनाया गया। 2026 तक पहुँचते-पहुँचते यह यात्रा केवल अधिकारों के संघर्ष की कहानी नहीं रही, बल्कि 'अस्तित्व से व्यक्तित्व' तक पहुँचने की प्रेरक गाथा बन चुकी है।

सामाजिक बदलावः अधिकारों का सार्थक उपयोग

आज की भारतीय महिला अपने अधिकारों के प्रति न केवल सजग है, बल्कि उनका उपयोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कर रही है। ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उभरी 'लखपति दीदी' जैसी पहल इस बात का प्रमाण है कि जब आर्थिक संसाधन महिलाओं के हाथ में आते हैं, तो पूरे समाज की तस्वीर बदल जाती है। जैसे रंग पंचमी पर हर रंग मिलकर एक उत्सव मनाते हैं, वैसे ही आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सम्मान मिलकर महिला के जीवन में खुशहाली के नए रंग भर रहे हैं। आज की महिला केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणादायक और रंगीन भविष्य का सृजन कर रही है।

2026 का संकल्पः भारत कैसे बनेगा समावेशी

समावेश की इस यात्रा को और तीव्र बनाने के लिए हमें तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

कौशल और तकनीकः महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और भविष्य की तकनीकों में अग्रणी बनाना।

डिजिटल न्यायः तकनीक का लाभ ग्रामीण भारत की हर बेटी के हाथ में पहुँचे।

समान अवसर का वातावरणः एक ऐसा सामाजिक तंत्र जहाँ प्रगति के मार्ग में कोई 'अदृश्य बाधा' (ग्लास सीलिंग) शेष न रहे।

मानवता का उत्कर्ष

2026 का यह महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि महिला सशक्तिकरण कोई अंतिम गंतव्य नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली एक यात्रा है। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ किसी लड़की को अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने के लिए संघर्ष न करना पड़े, बल्कि उसे जन्म से ही समान अवसर और खुला आकाश मिले। अवसर की समानता ही भविष्य की सबसे बड़ी पूँजी है। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है और उसे नेतृत्व का अवसर मिलता है, तो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा राष्ट्र और समूची मानवता एक कदम आगे बढ़ती है। क्योंकि जब आधी आबादी को पूरा आकाश मिलता है, तभी किसी राष्ट्र का भविष्य सच में ऊँची उड़ान भरता है।

वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES | MPIDC MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD. | इन्वेस्ट मध्यप्रदेश उद्योग एवं रोज़गार वर्ष 2025

मध्यप्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि का द्वार

देश का सबसे बड़ा 'पीएम मित्र' पार्क

धार, मध्यप्रदेश

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 5F विज़न

फार्म टू फाइबर । फाइबर टू फैक्ट्री । फैक्ट्री टू फैशन । फैशन टू फॉरेन

कम्पलीट वैल्यू चेन @ वन डेस्टिनेशन

कताई से लेकर सिलाई तक पूरी प्रक्रिया के लिये एकीकृत मेगा टेक्सटाइल पार्क

पार्क क्षेत्र - 2,158 एकड़

₹ 20 हजार करोड़ का निवेश सुनिश्चित

3 लाख लोगों को रोज़गार

टेक्सटाइल के क्षेत्र में लब्ध-प्रतिष्ठित 91 कंपनियों को निवेश प्रस्ताव के अनुरूप भूमि आवंटित

R.O. No. : D19345/25

फार्म से फॉरेन तक मध्यप्रदेश का वस्त्र उद्योग

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)